अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

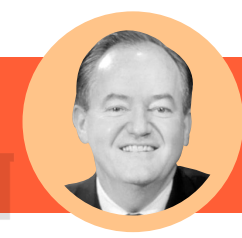

किसी के भी जीवन का सबसे बड़ा उपहार दोस्ती है...
...हर्बर्ट एच हम्फ्री, अमेरिकी राजनेता

अमेरिका द्वारा मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नया प्रस्ताव पेश करना और टेरर फंडिंग के खिलाफ फ्रांस द्वारा लाए प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में पारित होना आतंकवाद के खिलाफ बनते जनमत के ही सुबूत हैं।

पाकिस्तान के साथ घिरता चीन

सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रयास पर चौथी बार चीन के वीटो के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने अब जैश सरगना पर प्रतिबंध लगाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन से जिस तरह सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए प्रस्ताव का मसौदा पेश किया है, वह पाकिस्तान से ज्यादा चीन के लिए शर्मसार करने वाला है। इस पर आपत्ति लगाने जैसा नियम लागू नहीं होता। इसे पारित कराने के लिए पंद्रह सदस्यों में से नौ का समर्थन चाहिए और ज्यादातर देश प्रस्ताव के पक्ष में हैं। चीन इस पर फिर वीटो कर सकता है, पर इससे वह अलग-थलग पड़ जाएगा। इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन न सिर्फ आमने-सामने हैं, बल्कि आतंकी सरगना को सार्वजनिक तौर पर चीन बार-बार बचा भी नहीं सकता। भले वह भारत-विरोध तथा पाकिस्तान में किए गए अपने भारी निवेश के मद्देनजर यह रुख अपना रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ बनते वैश्विक जनमत के मद्देनजर उसे अपना रुख स्पष्ट करना होगा। जहां तक इस अमेरिकी तत्परता का सवाल है, तो इसके पीछे पाकिस्तान के प्रति भारत के सख्त रुख को भी कारण बताया जा रहा है, ताकि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाकर इस क्षेत्र में तनातनी की आशंका खत्म की जाए। इस बीच एक रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग का भी एक प्रस्ताव रखा है। अलबत्ता पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सक्रियता सिर्फ अमेरिका ही नहीं दिखा रहा। संयुक्त राष्ट्र में टेरर फंडिंग के खिलाफ लाया गया जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, और जिसमें कहा गया है कि हर देश में आतंकी संगठनों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून होना चाहिए, वह फ्रांस द्वारा लाया गया है। इन सबके बीच पाकिस्तान ने अपने यहां आतंकी अड्डे होने से इनकार

कर फिर बताया है कि वह बदलने वाला नहीं है। हालांकि वैश्विक आतंकी घोषित होने से जमीनी स्तर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। यह भी सच है कि आतंकवाद के मामले में असहयोग करने वाले देश अब तक दंडित नहीं हुए हैं। इन सबके बावजूद विकसित देश और संयुक्त राष्ट्र अगर आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहे हैं, तो यह भारत जैसे देशों के लिए उम्मीद जगाने वाली बात है, जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं।

विकास और जाति के बीच

बड़े वादे करके कांग्रेस क्या अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकेगी या फिर भाजपा कांग्रेस के नहले पर दहला मारने की तैयारी कर रही है? हालांकि देश का मतदाता तो सोच-विचार और मंथन के बाद ही कुछ तय करेगा।

मनीषा प्रियम
राजनीतिक विश्लेषक

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुए अब एक पखवाड़े से ऊपर बीत चुका है। चुनाव की घोषणा के ठीक बाद बहस इन मुद्दों पर थी कि क्या बालाकोट और पुलवामा मामले ही इस चुनाव पर हावी रहेंगे, जो सत्तारूढ़ दल को हावी बनाएंगे या बेरोजगारी और किसानी के मुद्दों की भी चर्चा होगी। दूसरी चर्चा यह गर्म रही कि सात चरणों की लंबी चुनावी अवधि में छोटे दलों का टिक पाना मुश्किल होगा। यह भी माना गया कि अमूमन सत्तारूढ़ दल को ही इसका कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन अब राजनीतिक बहस और नोक-झोंक तेज हो गई है। लगभग सभी दलों ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय दलों के साथ अपना गठजोड़ बना लिया है। चुनावी चर्चा की शुरुआत गठबंधन को महामिलावट या ठगबंधन बताकर हुई थी, पर यह तय है कि सबका हाथ किसी न किसी के साथ जुड़ा ही हुआ है। किस राजनीतिक दल ने कब किस नेता पर आक्षेप किया, किस मुद्दे पर किसने किसकी सरकारी गिराई-ये सारे मामले अब शोध का विषय हैं। वर्तमान यह है कि न तो कोई राष्ट्रीय दल और न ही कोई क्षेत्रीय दल अपने दम-खम पर इस चुनावी मैराथन में भाग लेने को तैयार है।

अब अगर राजनीतिक मामलों पर आएं, तो गठजोड़ की विविध शैली पर नजर घुमाना सबसे महत्वपूर्ण है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 80 लोकसभा सीटें दांव पर रहेंगी, सपा, बसपा और रालोद ने अपना गठबंधन समय पर घोषित कर दिया। लेकिन इसमें कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया और शालीनता के साथ केवल दो सीटें- रायबरेली व अमेठी-बख्श दी गईं, क्योंकि तय ही है कि यहां से क्रमशः सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अभी इस पर चर्चा आगे भी नहीं बढ़ी थी कि प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद रावण से जाकर मिलीं। रावण एक उभरते हुए दलित नेता हैं और युवा वर्ग में उनके लिए जुनून है। अगले ही क्षण मायावती का करारा बयान आया कि इस

गठबंधन की कांग्रेस से मेलजोल की अब कोई संभावना नहीं है। रही-सही कसर कांग्रेस ने पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बिजनौर से कांग्रेस का टिकट देकर पूरी कर दी। यानी विपक्षी दलों का पूर्ण गठबंधन होते-होते रह गया। वहीं भाजपा में भी अनुप्रिया पटेल ने दबाव बनाकर अपने सीटों की संख्या बढ़वाई। और आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस चुनाव में भाजपा के साथ है या विरोध में।

वहीं दूसरे बड़े राज्य बिहार में जाएं, तो वहां भाजपा, जदयू और लोजपा ने अपने गठबंधन की काफी पहले ही घोषणा कर दी। लालू यादव और कांग्रेस के पुराने संबंध रहे हैं, इसलिए लोगों का अनुमान था कि यह गठबंधन तो बड़ी आसानी से होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करती रही और जेल के भीतर बैठे लालू यादव ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कहीं ज्यादा सीटें दिलवा दीं। पूर्व में वामपंथी दलों के चहेते रहे लालू यादव जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार की बेगूसराय सीट पर दावेदारी पर नहीं माने और भाकपा की मांग उन्होंने खारिज कर दी। इन सबके बावजूद सबने यह स्वीकारा कि सबकी मुख्य चुनावी चुनौती नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। यानी लक्षित शत्रु होने के बावजूद आंतरिक प्रतिस्पर्धा बरकरार है।

भाजपा में भी टिकट बंटवारे को लेकर भरपूर घमासान छिड़ा है। बिहार में किसी एक अगड़ी जाति को जमकर टिकट दिए गए हैं, और इसी सवर्ण जाति (राजपूत) पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी अपना भरोसा जताया है। नतीजा यह है कि जहां एक हाथ से भाजपा ने अगड़ों को आरक्षण दिया है, वहीं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सवर्णों के बीच तोड़फोड़ की राजनीति को भी बढ़ावा दिया है। इसी दल के मंत्री रहे गिरिराज सिंह को अपनी परंपरागत सीट नवादा से हटाकर बेगूसराय भेज दिया गया है, जहां उन्हें कन्हैया कुमार और राजद के एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्र और मुरली मनोहर जोशी को चुनावी प्रक्रिया से दरकिनार कर दिया गया है।

अगर दक्षिण के राज्यों में जाएं, तो मेल-मिलाप का सबसे बड़ा संघर्ष तमिलनाडु में है, जहां कांग्रेस ने द्रमुक के साथ समझौता किया है, पर कैप्टन विजयकांत की पार्टी डीएमडीके को दरकिनार कर दिया है। वहीं भाजपा ने पन्नीरसेलवम और पलानीस्वामी के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक से गठबंधन किया है, पर अन्नाद्रमुक का एक मजबूत धड़ा शशिकला और दिनाकरन के पास है। दोनों ही द्रविड़ पार्टियों के दिग्गज नेता करुणानिधि और जयललिता का निधन हो गया है, ऐसे में तमिल उथल-पुथल के नतीजों पर अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

महाराष्ट्र में जहां भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है, वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने भी अपना समन्वय बना लिया है। सभी मानते हैं कि भाजपा और शिवसेना का पलड़ा भारी है, पर यह किसी को स्पष्ट नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ममता का तृणमूल है, जहां भाजपा भी अपनी दावेदारी ठोक रही है और अच्छे प्रदर्शन की आशा करती है। लेकिन वहां कांग्रेस और वाम दलों के लिए भी अस्तित्व बचाने का मामला है। ममता को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या वह गठबंधन की सबसे प्रमुख नेत्री बनी रहेंगी और क्या भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने पांव जमा पाएगी, इन्हीं सवालों से वहां की चुनावी चर्चा गर्म है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस 'एकला चलो रे' की नीति अपना रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने कई पुराने प्रत्याशियों को बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या प्रत्याशी बदलने से राजनीतिक दिशा बदल जाएगी।

इस राजनीतिक कोलाहल के बीच राहुल गांधी ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक एलान न्यूनतम आय के नाम पर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या बड़े वादे करके कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकेगी या क्या कांग्रेस के नहले पर भाजपा किसी दहले की तैयारी कर रही है। इस सबके बीच देश का मतदाता अभी सोच रहा है। सोच-विचार और मंथन की प्रक्रिया के उपरांत ही चुनाव में वह अपनी मुहर लगाएगा।

मैं मिजो महिलाओं की स्थिति बदलना चाहती हूं

अपनी कहानी
>> ललथलामौनी

मिजोरम के संसदीय चुनाव के इतिहास में राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट से पहली महिला उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए मैं बहुत रोमांचित महसूस कर रही हूं। मेरा मानना है कि राजनीति लोगों और ईश्वर की सेवा का अवसर प्रदान करती है।

मैं 63 वर्षीय महिला और पांच बच्चों की दादी मां हूं। मैंने मात्र दसवीं तक शिक्षा हासिल की है। सत्ता या नाम के लिए मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा है। लोगों और ईश्वर की सेवा के लिए मैं इस क्षेत्र में आई हूं। महिला शिक्षा दर ज्यादा होने के बावजूद मिजोरम का समाज पितृसत्तात्मक है। मैं इस तस्वीर को बदलना चाहती हूं। मिजोरम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन विधायी निकायों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। मैं अपने राज्य की महिलाओं के सामने यह उदाहरण पेश करना चाहती हूं कि अगर मेरी जैसी साधारण और कम पढ़ी-लिखी महिला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, तो वे क्यों नहीं। जिस दिन मिजोरम की महिलाओं को अपनी क्षमता का एहसास हो जाएगा, उसी दिन वे राज्य की तस्वीर बदल देंगी।

पहले भी लड़ा है चुनाव

इस बार मैं ईश्वर के इशारे पर राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हूं, जहां मेरा सामना पांच पुरुष प्रत्याशियों से है। इससे पहले मैंने पिछले वर्ष (2018 में) विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई थी। इसकी मुख्य वजह समाज का पुरुष वर्चस्ववादी ढांचा और महिलाओं में राजनीतिक चेतना का अभाव है। वे समझती हैं कि राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है, जबकि राज्य की महिलाएं जीवन के बाकी हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं।

मेरा मुख्य चुनावी एजेंडा

मैं वर्तमान में छिनलुंग इस्राइल पीपुल्स कन्वेंशन (सीआईपीसी) का नेतृत्व कर रही हैं। यह समूह देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे यहूदी समुदाय की एकता के लिए संघर्ष कर रहा है। मिजोरम लगभग 20,000 यहूदियों का घर है। मैं चाहती हूं कि केंद्र में हमारे समुदाय की आवाज सुनी जाए। मेरा मुख्य चुनावी एजेंडा संयुक्त राष्ट्र को सौंपे गए एक ज्ञापन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना है, जिसमें हमारे समुदाय को इस्राइल की एक खोई हुई जनजाति के रूप में मान्यता दिलाने की मांग की गई है। अगर मैं चुनाव जीतती हूं, तो अपने समुदाय की पहचान और महिलाओं व किसानों की स्थिति में सुधार के लिए काम करूंगी।

भारत-इस्राइल संबंधों को मजबूत बनाने की इच्छा

मेरी इच्छा है कि भारत और इस्राइल के संबंध और मजबूत बनें। मेरे चुनाव लड़ने का एक कारण यह भी है। चुनाव जीतने पर मैं इस दिशा में भी काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि मिजो-यहूदी समुदाय के लोगों को इस्राइल की पवित्र भूमि पर जाने का अवसर मिले।

महिलाओं का समर्थन

चूंकि मैं ईश्वर के संकेत पर चुनाव लड़ रही हूं, सत्ता व नाम के लिए नहीं, बल्कि मिजो समुदाय, महिलाओं और किसानों की सेवा करने के संकल्प के साथ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार चुनाव जीतूंगी। इसके अलावा सीआईपीसी के पूरे राज्य में एक लाख से ज्यादा सदस्य हैं, इन लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा और एकमात्र महिला प्रत्याशी होने के नाते महिलाओं का भी मुझे भरपूर समर्थन मिलेगा। इसलिए मुझे अपना चुनाव जीतने पर पूरा भरोसा है।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित

फैक्ट फाइल

भारत निर्वाचन आयोग

>> निर्वाचन सदन

25 जनवरी, 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त सांविधानिक संस्था है, जिस पर देश में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी होती है। वह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के साथ ही राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के भी चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 (4) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत काम करता है। उसके पास चुनाव करवाने से संबंधित नियम बनाने के अधिकार हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। इसलिए 25 जनवरी को देश में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुकुमार सेन देश के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। स्थापना के बाद 1989 तक निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। 1989 में निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम के जरिये आयोग को बहुसदस्यीय संस्था में बदल दिया गया। 16 अक्तूबर, 1989 को आयोग में पहली बार दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। चुनाव सुधारों में निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका है। आयोग नियमों के तहत राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है और उन्हें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पंजीकृत दलों के रूप में मान्यता देता है। चुनाव के दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है। इसके लिए वह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है और उसके पर्यवेक्षक इस पर नजर रखते हैं।

यूरोप की सड़कों पर गति नियंत्रण

सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यूरोपीय संघ सभी कारों को नई तकनीकों से लैस करने पर विचार कर रहा है।

व्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पाल्को कैरेज

यूरोपीय संघ सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2022 तक नई कारों के तमाम मॉडलों में गति सीमा और आपातकालीन ब्रेक लगाने की तकनीक के अलावा दर्जन भर और तकनीकों को आवश्यक करने की एक योजना पर विचार कर रहा है। इसकी घोषणा यूरोपीय संसद ने की है। स्पीड लिमिटिंग टेक्नोलॉजी में, जिसे इंटेलिजेंट स्पीड एसिस्टेंस कहा जाता है, वीडियो कैमरे या सैटेलाइट डाटा या फिर दोनों का इस्तेमाल होता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्राइवर गति सीमा का अतिक्रमण कर रहा है या नहीं। अगर वह सचमुच सीमा का अतिक्रमण करता पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसके वाहन की गति पर अंकुश लगाया जा सकता है। यूरोपीय संसद के अनुसार, इस तकनीक से यूरोपीय संघ की सड़कों पर दुर्घटनाओं में बीस फीसदी की कमी आएगी। अभी इस योजना को यूरोपीय संघ की कमेटी ने ही मंजूरी दी है। यह कानून तभी बनेगा, जब इसे यूरोपीय संसद और सभी सदस्य देशों के मंत्रियों की तरफ से मंजूरी मिलेगी।

एक गैरसरकारी संस्था यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी

काउंसिल के कार्यकारी निदेशक एंटोनियो एवेनोसो कहते हैं, 'यूरोप में पिछले पचास साल में ऐसे मौके कम ही आए हैं, जब सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर संजीदा कदम उठाए गए हों। अगर मौजूदा प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो पंद्रह साल में कम से कम 25,000 लोगों को बचाया जा सकेगा।' दुर्घटनाओं और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यूरोपीय संघ के अलग-अलग देशों में गति सीमा के अलग-अलग नियमों से समस्या ही बढ़ी है। मसलन, जर्मनी में गति सीमा तय करने के मामले में लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने ऐसा नियम लागू करने से इनकार कर दिया है। जबकि फ्रांस में एक ही सड़क पर अच्छे और बुरे मौसम में वाहनों की गति सीमा अलग-अलग है। हालांकि हाल ही में दो लेन वाली सड़कों पर गति सीमा कम किए जाने के आदेश पर फ्रांस के येलो वेस्ट आंदोलनकारियों ने भारी उत्पात मचाया और देश के आधे से अधिक स्पीड लिमिट कैमरों को सड़कों से हटा दिया।

लेकिन यूरोपीय संघ सड़क सुरक्षा के मामले में गंभीर है। वर्ष 1998 में इसने सभी सदस्य देशों के लिए क्रैश टेस्ट के समान मानक बनाए, तो 2006 में इसने सभी कारों में सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया। इसके बावजूद 2017 में यहां वाहनों की तेज गति के कारण 25,300 मौतें हुईं, तो 1,35,000 लोग घायल हुए। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल के प्रवक्ता डडली कर्टिस कहते हैं, 'दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों का निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे वाहनों की गति नियंत्रित रहे। इसके अलावा गति सीमा तय करने और तकनीक का इस्तेमाल करने की भी जरूरत है।' कर्टिस का कहना है कि यूरोपीय संघ जिस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, वह नया नहीं है। कुछ कार निर्माता पहले से ही अपनी कारों को इन तकनीकों से लैस कर रहे हैं, जिससे गति नियंत्रित रहे। कर्टिस यह भी कहते हैं कि नई तकनीकों वाली कारें यूरोप के समृद्ध देशों में पहले आएंगी और गरीब देशों में बाद में।

इस हफ्ते के शब्द

साइरस पूनावाला

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को टीका के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सम्मानित करेगा।

साइकिलिस्ट (CYCLIST)

ऑस्ट्रेलियाई शिक्षाविदों ने इस शब्द को प्रतिबंधित करने की मांग की है, क्योंकि यह शब्द साइकिल चलाने वालों के प्रति आक्रामकता बढ़ाता है।

लंबित मामले

57,785

लंबित मामले हैं सर्वोच्च न्यायालय में इस समय, जिनमें से 13,257 मामले अभी सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं।

सूत्र
>> सारा ब्लाकली

अरुचिकर काम भी पहचान बनाने में मदद करते हैं

मैं फ्लोरिडा में पैदा हुई। मेरे पिता एटॉर्नी थे, जबकि मां कलाकार। मेरा स्कूली जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। मैंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में डिग्री ली। मेरा भाई कलाकार बन गया था। मेरी इच्छा पापा की तरह एटॉर्नी बनने की थी, लेकिन मेरी यह इच्छा धरी की धरी रह गई। हताशा में कुछ महीने मैंने ऑरलैंडो में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में काम किया। उस दौरान कुछ समय तक मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन की भी भूमिका निभाई। फिर मैंने ऑफिस के लिए सामान उपलब्ध कराने वाली कंपनी डैंका जॉइन कर ली, जहां मैंने सात साल तक काम किया। उस दौरान मैंने घर-घर जाकर फैक्स मशीनें बेचने का काम किया, जो काफी कष्टकर था। मैं वह काम छोड़ देना चाहती थी। लेकिन घरवालों और दोस्तों ने यह काम जारी रखने के लिए कहा। मेरे अंदर कहीं न कहीं एक बेचैनी-सी थी कि मैं अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रही हूं। वह पहचान, जो मुझे दूसरों से अलग करती हो। उस कष्टकर काम ने ही मेरे लिए नई राह बनाई। दरअसल दरवाजे-दरवाजे घूमते हुए मैं जो कपड़े पहनती थी, वे फ्लोरिडा जैसी गर्म जगह में बेहद कष्टकर थे। उन्हीं दिनों एक पार्टी में जाने से पहले मैंने खुद ही अपने अंतरंग वस्त्र को काटकर छोटा कर दिया और स्लैक्स के नीचे उसे पहनने पर मुझे काफी आराम मिला। वहीं से अंतरंग परिधानों की कंपनी शुरू करने का मुझमें विचार आया। लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने दो साल और उसी कंपनी में काम किया और उस दौरान में अंतरंग वस्त्रों के बारे में तरह-तरह की जानकारी भी इकट्ठा करती रही।

उसके बाद नॉर्थ कैरोलिन जाकर, जो होजियरी मिलों के लिए विख्यात है, मैंने अलग-अलग लोगों से मुलाकात की और अंतरंग वस्त्रों के बारे में अपना आइडिया साझा किया। वहां ज्यादातर लोगों ने मेरे विचार को खारिज कर दिया। लेकिन वहां से लौटने के दो सप्ताह बाद एक मिल से मेरे पास चिट्ठी आई कि वह मेरे आइडिया पर अमल करने के लिए तैयार है। दरअसल उस मिल मालिक की तीन बेटियों को मेरा आइडिया बेहद पसंद आया था। उसके थोड़े ही दिनों बाद मैंने अटलांटा, जॉर्जिया में अंतरंग परिधानों की एक कंपनी स्पैनक्स की स्थापना की। अपनी जिंदगी से मैंने यही सीखा है कि कोई भी काम, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, करने से कभी मना नहीं करना चाहिए।

कोई भी काम, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, करने से कभी मना नहीं करना चाहिए। कई बार वहीं से सफलता के रास्ते निकल आते हैं।